भाग होने के कारण, कृषि अर्थशास्त्र में अध्ययन और अनुसन्धान करने वाले विश्वविद्यालयों, सरकारी विभागों और अनुसन्धान शालाओं से प्रार्थना की थी कि वे इस सम्मेलन में निमन्त्रण देने के लिये कृषि अर्थशास्त्रियों के नामों का सुझाव दें ।

Shri Subodh Hansda: What is the benefit that has accrued from this conference?

Shri M. V. Krishnappa: It is a conference of international agricultural economists and professors who are very learned men in their field and the very meeting of such great professors on Indian soil—for the first time they have met in Mysore in India—we feel, when they put their heads and pool their resources together, will be very much beneficial.

Shri Shree Narayan Das: May I know whether there is any national conference of this nature associated with this international conference and, if so, what is that body?

Shri M. V. Krishnappa: There is a Society of Indian Agricultural Economics. The Government of India and the Society of Indian Agricultural Economics acted as hosts to this conference.

Shri Tangamani: How many Indian agricultural economists were invited to this conference as delegates or as observers?

Shri M. V. Krishnappa: About 63 of them had been invited and more than 50 had taken part in the conference.

दिल्ली में भूमि की चकबन्दी

*६५६. **श्री नवल प्रभाकर:** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के कितने गांवों में भूमि की चकबन्दी हो चुकी है; और

(ख) बाकी गांवों में चकबन्दी का काम कब तक पूरा हो जाने की आशा है ?

कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) २१०.

(ख) बाकी गांवों में अगले वित्त वर्ष के शुरू में भूमि की चकबन्दी का काम आरम्भ करने की उम्मीद है और उसके बाद लगभग दो वर्षों में यह पूरा होगा ।

श्री नवल प्रभाकर: क्या मैं जान सकता हूं कि जब यह चकबन्दी का काम शुरू किया गया था तो क्या उसके लिये कोई नियम बनाये गये थे ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन): चकबन्दी के लिये पहले से नियम बने हैं ।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि जब नियम बना लिये गये थे और उनमें बीच में रास्ता छोड़ने की बात थी, तो दिल्ली में चकबन्दी करते वक्त जो बहुत से गांवों में रास्ते नहीं छोड़े गये हैं, इसका क्या कारण है ?

श्री अ० प्र० जैन : यह मैं नहीं कह सकता कि रास्ते नहीं छोड़े गये। जरूर छोड़े गये होंगे। लेकिन यह इतनी तफसील की बात है कि मेरे लिये इसका जवाब देना असम्भव है ।

श्री स० म० बनर्जी : जिस तरह से यह चकबन्दी का कार्य किया जा रहा है उसके खिलाफ काफी आवाज सिर्फ दिल्ली में नहीं उठ रही है, पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी है । तो क्या प्रान्तीय सरकारों ने आप के पास इस बारे में कुछ लिखा है और क्या वह आप के जेरे गौर है ?

श्री अ० प्र० जैन : चकबन्दी का काम पूरा राज्य सरकार के हाथ में है । हम ने तो खाली उन से इस बात की सिफारिश की है कि चकबन्दी जल्दी से जल्दी करें किस तरह से करें, क्या उस के नियम हों, किस के जरिये से करें, यह बिल्कुल उन के अख्तियार में है, इस के बारे में हम कोई दखल नहीं देते ।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि जो चकबन्दी के अधिकारी हैं वे हर साल बदल दिये जाते हैं ?

श्री अ० प्र० जैन : इन बातों का जवाब मैं कैसे दे सकता हूं ?

श्री बाल्मीकी : क्या माननीय मंत्री जी की जानकारी में यह बात है कि जैसे और देशों में चकबन्दी चलती है उस में उत्तर प्रदेश मे हरिजनों के रहने की जगह छोड़ी जाती है । लेकिन दिल्ली में जब कि चकबन्दी चल रही है तब उन की रिहायशी जगहों को हानि पहुंचने की सम्भावना हो गई है, और उन के लिये जगह नहीं छोड़ी जा रही है, और क्या मंत्री महोदय इस के लिये कुछ करना चाहते हैं ?

Mr. Speaker: He does not know. That is the very question that was put. So far as the details are concerned, he does not know. The hon. Member will put a separate question.

Shri P. S. Daulta: For Delhi he should know.

Mr. Speaker: Every detail he may not know. A separate question may be put down.

Fruit and Vegetable Development Board.

\+
*961. Shri Bhakt Darshan:
Shri Naval Prabhakar:
Sardar Iqbal Singh:

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 349 on the 23rd November, 1956 and state the progress so far made by the Fruit and Vegetable Development Board which was set up under the Indian Council of Agricultural Research?

The Deputy Minister of Agriculture (Shri M. V. Krishnappa): A Fruit and Vegetable Development Committee was constituted in December, 1956, in order to deal with matters of general policy in respect of research development, marketing and preservation of fruits, vegetables and flowers. Two meetings of this Committee have so far been held, the first in March, 1957 and the second in December, 1957. The status of this Committee has now been raised to that of a Board and it has been redesignated as 'Horticulture Development Board'.

Shri Jagdish Awasthi: The original question was put in Hindi. He should reply in Hindi.

Mr. Speaker: He wants the Hindi answer.

श्री अ० प्र० जैन : फल, सब्जी, और फूलों के अनुसन्धान, विकास, पणन और परिरक्षण सम्बन्धी सामान्य नीति के मामलों पर कार्य करने के लिये दिसम्बर १९५६ मे एक फल और सब्जी विकास समिति बनाई गई थी । इस समिति की अभी तक दो बैठकें हुई हैं, पहली मार्च, १९५७ मे और दूसरी दिसम्बर, १९५७ मे । अब इस समिति का पद एक बोर्ड का कर दिया गया है और इसका नाम "उद्यान विकास बोर्ड" कर दिया गया है ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, मैं जानना चाहता हू कि जो पहले वह समिति थी और अब उसे बोर्ड बना दिया गया है, उस ने क्या सारे देश मे फल और तरकारियों के विकास के लिये कोई ठोस योजना बनाई है, और अगर बनाई है तो उस की रूप रेखा क्या है ?

श्री मो० वे० कृष्णप्पा : उस के उद्देश्य मैं टेबल पर रखता हू ।

श्री भक्त दर्शन : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस बोर्ड के पास कोई धनराशि रखी गयी है ताकि वह सीधे या राज्य सरकार की सहायता से इस काम को आगे बढ़ाये । और यदि रखी गयी है तो इस काम के लिये कितनी रकम है ?

श्री अ० प्र० जैन : यह बोर्ड इंडियन कौंसिल आफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के नीचे